कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) सौ (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वंय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकारों के बीच अंतर विभागीय विवादों में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) मणिपुर राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को उसके जल संसाधनों के विकास के लिए उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(च) परियोजना कार्यों को शीघ्र करने के लिए वर्ष 1996-97 एंव 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) दी गई है:

परियोजना	लाभान्वित जिले	वर्ष 1996-97 के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ों रुपये में)
खुग	चुराचांदपुर	4.3	6.0
थौबल	इम्फाल उखल्ल सेनापति, थौबल	शून्य	20.0

Withdrawal/Modification of DOP& T Memoranda Regarding SC/ST Employees

*529. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether certain Office Memoranda were issued by the Department of Personnel and Training on 30th January, 2nd July, 22nd July, 13th August and 29th August, 1997 contaning the directions which have adversely affected the recruitment and promotional career of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees;

(b) whether the All-India Confederation of SC/ST Organisations had made representations to the Prime Minister and the Home Minister for withdrawal/modification of the above office memoranda; and

(c) if so, what action Govemment have taken/or propose to take on the above representations for withdrawing/modifying the said office memoranda?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) All these Office Memoranda, except the Office Memorandum dated the 13th August, 1997, on different aspects of the reservation policy, have been issued in implementation of various judgements of the Supreme Court. The Office Memorandum dated August 13, 1997, issued in pursuance of Article 16 (4A) of the Constitution, continues reservation in promotions which, otherwise, would have ceased after November 15, 1997.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise, in view of (a) above.

किसानों को घिटाया किस्म के बीजों का विवरण

*530. श्री औकार सिंह लखावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में किसानों को नकली और घटिया किस्म के बीज विवरण की शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किये गए, और

(ग) वर्ष 1998 में खरीप और रबी की फसल हेतु राजस्थान के लिए उन्नत किस्म के बीजों के विवरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने मिलावटी तथा घटिया किस्म के बीजों की शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है। दर्ज किये गए मामलों की संख्या का ब्यौरा विवरण-1 में है (नीचे देखिए)

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1997-98 में राज्य सरकारों द्वारा मिलावटी और घटिया बीजों की आपूर्ति के बारे में प्राप्त की गई शिकायतों का विवरण

क्रम राज्य सरकार सं. का नाम	**घटिया बीजों की आपूर्ति की शिकायतों / मामलों की संख्या**
1. आन्ध्र प्रदेश	4 संख्या
2. असम	उ.न.
3. बिहार	उ.न.
4. गुजरात	2 संख्या
5. हरियाणा	उ.न.
6. हिमाचल प्रदेश	शून्य
7. जम्मू एंव कश्मीर	उ.न.
8. कर्नाटक	11 संख्या
9. केरल	शून्य
10. मध्य प्रदेश	शून्य
11. मेघालय	उ.न.
12. महाराष्ट्र	18 संख्या
13. मणिपुर	उ.न.
14. मिजोरम	उ.न.
15. नागालैण्ड	उ.न.
16. उड़ीसा	शून्य
17. पंजाब	शून्य
18. राजस्थान	10 संख्या
19. तमिलनाडु	2 संख्या
20. त्रिपुर	शून्य
21. उत्तर प्रदेश	उ.न.
22. पश्चिम बंगाल	शून्य
23. अरूणाचल प्रदेश	उ.न.
24. गोवा	शून्य
25. सिक्किम	शून्य
उ.न. – उपलब्ध नहीं।	

विवरण – II

राजस्थान में खरीफ 1998 तथा रबी 1998-99 के लिए बीजों के विवरण का निर्धारित लक्ष्य।

क्र. सं. खरीफ	मात्रा क्विंटल में
1. बाजार	47,000
2. मक्का	7,000
3. ज्वार	4,1100
4. धान	2,000
5. मूंग	6,000
6. उड़द	11,500
7. मोठ	750
8. लोबिया	800
9. अरहर	800
10. तिल	1,400
11. मुंगफली	6,000
12. अरण्डी	800
13. सोयाबीन	16,500
14. कपास	40,000
15. ग्वार रबी	1,300
16. गेहूं	2,00,000
17. चना	15,500
18. सरसों	33,000
19. जौ	3,100
20. मसूर	150

Central Team for KBK Districts in Orissa

*531. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Govemment had sent a Central team to the KBK (Kalahandi, Bolangir and Koraput) districts in Orissa;

(b) if so, what kind of assessment was made in KBK districts; and

(c) the details of the action taken on the study report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir. The Ministry of Water Resources had constituted a Team of Officers in July, 1997 to assess drought situation in Kalahandi and other districts of Orissa and suggest remedial measures. The Team visited the area and reviewed the status of ongoing drought alleviation projects and new projects which have been identified by the State Govemment for implementation.